आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 22.11.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के वादे के साथ देश में नई श्रम संहिताएँ लागू।
- राज्य सरकार ने 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस शुल्क बढ़ोतरी को एक वर्ष के लिए स्थगित किया।
- राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानव–भालू संघर्ष की घटनाएं बढ़ने पर सरकार सतर्क; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भालू के हमलों पर तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश।
- देहरादून में आयोजित प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन–2025 के दूसरे दिन अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों की बेहतर पहलों पर प्रस्तुतिकरण दिए।

श्रम कानून संहिता लागू

केंद्र सरकार ने देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से चार नई श्रम संहिताओं को आज से लागू करने की घोषणा की। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ० मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। वेतन संहिता–2019, औद्योगिक सम्बंध संहिता–2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता–2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता–2020 शुक्रवार से लागू हो गई हैं।

शुल्क बढोतरी स्थगित

राज्य सरकार ने 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस शुल्क बढ़ोतरी को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। अब 21 नवम्बर 2026 तक पुरानी फीस ही लागू रहेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को बढ़ी हुए शुल्क का तुरंत बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में काफी बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने जनभावनाओं को देखते हुए इस बढ़ोतरी को तत्काल लागू न करने

का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ने देना चाहती और भविष्य में नई फीस दरें केंद्र द्वारा किए जाने वाले पुनरीक्षण के बाद ही लागू होंगी।

<u>एकता रैली</u>

अल्मोड़ा में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा ने राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम के तहत एकता रैली निकाली। रैली नंदा देवी मंदिर परिसर से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए शहीद तिराहा और मॉल रोड तक पहुंची। कार्यक्रम में अल्मोड़ा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, भाजपा प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बलवीर गुनिया, भाजपा प्रदेश मंत्री गौरव पांडे और विभिन्न स्कूलों के छात्र–छात्राओं ने भाग लिया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि देश की स्वतंत्रता और एकता को मजबूत करने में सरदार पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

<u>कार्रवाई</u>

हरिद्वार में जिला प्रशासन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने सीएससी सेंटरों की निगरानी तेज कर दी है और इसी क्रम में एक संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

उप जिलाधिकारी हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने बताया कि तहसीलदार की जांच में एक सीएससी केंद्र संचालक द्वारा फर्जी खतौनी लगाकर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कराने का मामला सामने आया। जांच में पाया गया कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई खतौनी वास्तविक अभिलेखों से मेल नहीं खाती थी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर पिछले पांच वर्षों में जारी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। साथ ही वर्तमान में जारी हो रहे सभी प्रमाण पत्रों की भी गहन जांच होगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले किसी भी सीएससी संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

<u>मानव–वन्यजीव संघर्ष</u>

उत्तराखंड के अलग–अलग इलाकों में हाल ही में मानव–भालू संघर्ष की घटनाएं बढ़ने पर सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भालू के हमलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। वन मंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक रिपोर्ट–

मानव–भालू और मानव–गुलदार संघर्ष से जुड़े हालिया मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण ने प्रभावित क्षेत्रों के सभी प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मानव–वन्यजीव संघर्ष के समाधान के लिए किये गये प्रयासों की जानकारी ली गई और इस समस्या का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समाधान करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रमुख वन संरक्षक ने अधिकारियों से कहा कि मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रभाग स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को भालू और गुलदार से बचाव से जुड़ी जानकारी दी जाए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और कैमरा ट्रैप, ड्रोन आदि उपकरणों का अधिक उपयोग करने को कहा, ताकि वन्यजीवों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके।
आकाशवाणी देहरादून के लिये समाचार कक्ष से अमित सुन्द्रियाल

<u>प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन–2025</u>

देहरादून में आयोजित प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन–2025 का दूसरा दिन मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान कई जिलाधिकारियों ने अपने जिलों की बेहतर पहलों पर प्रस्तुतिकरण दिए, जिन पर अधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की।

अल्मोड़ा की जिलाधिकारी ने खेल स्वास्थ्य और वेलनेस पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं देने और नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए खेल एवं सामुदायिक फिटनेस क्षेत्र बनाया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 100 बच्चों को मुफ्त कोचिंग और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पौड़ी की जिलाधिकारी ने पिरूल और इनवेसिव बायोमास पर आधारित आजीविका मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पिरूल से बायोमास तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें नियमित आय मिल रही है और वनाग्नि व जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल रही है। इसमें 280 महिलाएं शामिल हैं।

वहीं, नैनीताल के जिलाधिकारी ने शहरी बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी पर प्रस्तुतीकरण दिया और शहर के लिए सतत विकास का रोडमैप रखा। मुख्य सचिव ने सभी नगर निकायों को इसी तरह का रोडमैप बनाने के निर्देश दिए।

<u>प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन–2025 जारी</u>

बैठक में देहरादून के जिलाधिकारी ने बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम पर जानकारी दी। शहर में ऐसे बच्चों के लिए एक केंद्र बनाया गया है, जहां उन्हें पढ़ाई, खेल और कौशल विकास जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि उन्हें भिक्षावृत्ति से बाहर लाया जा सके। नगर आयुक्त ने भी शहर की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार किए गए मॉडल का प्रस्तुतीकरण दिया।

टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी ने युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास पर किए जा रहे कामों की जानकारी दी। उन्होंने कैप्सूल कोर्स, मोबिलिटी सपोर्ट, करियर हब और फ्लेक्सिबल स्किलिंग पाथवे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

वहीं, उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने धराली आपदा में हुई क्षति और भविष्य में रोकथाम के प्रयासों पर प्रस्तुतीकरण दिया, साथ ही पारिस्तिथिकी और आजीविका पर आधारित प्रोजेक्ट की जानकारी दी, जिसकी सराहना की गई।

मुख्य सचिव ने खेल, हरित आजीविका और युवाओं के सशक्तिकरण से जुड़े अभिनव मॉडल की प्रशंसा की और अधिकारियों को बेस्ट प्रैक्टिसेज को आगे बढ़ाने तथा भविष्य की योजनाओं को विकसित उत्तराखंड 2047 के लक्ष्य से जोड़ने के निर्देश दिए।

स्वच्छता अभियान

हरिद्वार में जिला प्रशासन का स्वच्छता अभियान कल तीसरे दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित पूरे जिले को स्वच्छ, और मॉडल जिला बनाने के प्रयासों की स्वयं निगरानी कर रहे हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर एन.एच.ए.आई की टीम ने दुधाधारी फ्लाईओवर, गुरुकुल नारसन, बहादराबाद बाईपास और कोर कॉलेज के पास सड़क किनारों की सफाई की। खानपुर ब्लॉक में पुरकाजी बॉर्डर से एकत्र कूड़े को कॉम्पेक्टर तक पहुंचाया गया और ग्राम पंचायत सिकंदरपुर स्थित कॉम्पेक्टर का निरीक्षण किया गया। लक्सर ब्लॉक में भी सफाई अभियान चलाया गया, जिसका निरीक्षण खंड विकास अधिकारी ने किया।

श्यामपुर वन क्षेत्र में वन विभाग ने एनएच–34 के पास सफाई की। वहीं हरकी पैड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें वाल्मीकि मंदिर और नाई घाट पर लगे अतिक्रमण हटाए गए।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर सफाई कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। अभियान का असर दिखाई देने लगा है और शहर से ग्रामीण इलाकों तक लगातार सफाई कार्य किया जा रहा है।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर——

देश में नई श्रम संहिताएं लागू करने की ख़बर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में हैं। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– न्यूनतम वेतन की गारंटी लागू, केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून अधिसूचित किए, चालीस करोड़ कर्मचारियों को लाभ। इसी ख़बर पर दैनिक जागरण समाचार पत्र की सुर्खी है– महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन; फिक्सड टर्म कर्मियों को एक वर्ष नौकरी के बाद ग्रेच्युटी।

देहरादून में चल रहे प्रशासननिक अधिकारी सम्मेलन की ख़बर पर अमर उजाला ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन के निर्देशों को अपनी सुर्खी बनाया है। समाचार पत्र लिखता है– ज़िलों में सर्वोत्तम पहल राज्यभर में लागू की जाएं।

भालू के मामलों पर सीएम के त्वरित कार्रवाई के निर्देश, दैनिक जागरण की सुर्खी है। समाचार पत्र के अनुसार मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के लिये उपकरणों की खरीद हेतु वन प्रभागों को पचास लाख रुपए आवांटित किए जा रहे हैं।